

प्रेषक,

विनीता कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग,  
देहरादून।

सनाज कल्याण अनुभाग-01,

देहरादून 20 अगस्त 2007.

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-599/XXVII(1)/ 2007, दिनांक 12 जुलाई 2007 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए एवं शासनादेश संख्या-243/XVII(1)-01/2007-10(22)/2006, दिनांक 24 अप्रैल 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित (माह अप्रैल 2007 से जुलाई 2007 के लेखानुदान की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) संलग्नक-01 के अनुसार रुपये 40,22,000/- (रुपये चालीस लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो।
2. वित्तीय वर्ष 2007-08 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण की सूचना पृथक से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
3. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाए।
4. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, बजट मैनुअल तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही हैं।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाए।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
10. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
11. बी.एम.-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों तथा मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की "अनुदान संख्या-30" के अन्तर्गत संलग्नक-01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-183(NP)/XXVII(3)/2007, दिनांक 16 अगस्त 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII(I)-01/2007-10(22)/2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
8. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह निबियाल)  
अपर सचिव।



1. अनुदान संख्या-30

आयोजनेत्तर

- लेखाशीर्षक : 2225-01-001-08-00  
 मुख्य शीर्षक : 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  
 उप मुख्य शीर्षक : 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण  
 लघु शीर्षक : 001-निर्देशन तथा प्रशासन  
 उप शीर्षक : 08-अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय  
 व्यौरेवार शीर्षक : 00-

(धनराशि हजार रुपये में)	
मानक मद	धनराशि
01-वेतन	1293
03-महंगाई भत्ता	775
04-यात्रा व्यय	67
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	24
06-अन्य भत्ते	143
07-मानदेय	300
08-कार्यालय व्यय	50
09-विद्युत देय	30
10-जलकर/जलप्रभार	5
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	35
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7
13-टेलीफोन पर व्यय	75
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	186
18-प्रकाशन	17
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	17
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	9
42-अन्य व्यय	17
45-अवकाश यात्रा व्यय	25
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20
48-महंगाई वेतन	647
योग	4022

(रुपये चालीस लाख बाईस हजार मात्र)

(अजय सिंह त्रिबियाल)  
 अपर सचिव।